

# संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता के लिए जी-4 देशों का

**प्रयत्न :-** डॉ मंजू आचार्य

व्याख्याता राजनीति विज्ञान विभाग

एस एस जैन सुबोध गर्ल्स पी. जी. कॉलेज

सांगानेर जयपुर.

जर्मनी, जापान, ब्राजील व भारत तथाकथित जी-4 देशों के समूह ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की न्यूयार्क में प्रस्तावित बैठक से पूर्व सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु अपनी संयुक्त प्रयासों का शुभारम्भ किया। चारों देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि नये वैश्विक खतरों के मद्दे नजर सदस्यता विस्तार की बेहद सख्त जरूरत है इसीलिए वे अपनी सांझा दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। घोषणा में आगे कहा गया कि जर्मनी, ब्राजील, भारत व जापान जिनको जी-4 राष्ट्र कहा जाता है वे परस्पर उम्मीदवारी का एक दूसरे को समर्थन प्रदान करते हैं व उनकी मान्यता है कि स्थायी सदस्यता के लिए वे योग्य उम्मीदवार हैं। सुरक्षा परिषद को 21 वीं सदी के विश्व समुदाय की यथार्थवादी स्थितियां व वास्तविकता प्रतिबिंबित करनी होगी। घोषणा में संयुक्त राष्ट्र में उठ रहे विभिन्न सुरो को चिन्हित करते हुए जिनमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान भी शामिल है कहा गया 15 देशों की परिषद का विस्तार इसके द्वारा लिये गये निर्णयों को नैतिक आधार पर बल प्रदान करेगा। विश्व समुदाय विभिन्न खतरों व चुनौतियों से प्रभावशाली रूप से निपट सके इसके लिए समूचे संयुक्त राष्ट्र में सुधार किया जाना आवश्यक था। परिषद विस्तार से संबंधित प्रस्ताव जो कि संयुक्त राष्ट्र के 191 सदस्य देशों पर बंधनकारक रहेगा यह प्रस्ताव लम्बे समय से पारित नहीं हो पाया है। अतः परिषद में वीटो पॉवर के साथ वे ही □□□□ स्थायी सदस्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अग्रणी बने थे। दस और राष्ट्र को अस्थायी सदस्यों को 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रीय व्यवस्था से चुना जाता है।<sup>1</sup>

## प्रस्तावित सुधार 60 वर्ष के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण

चार देशों द्वारा रखे गये प्रस्ताव में अफ्रीका के लिए एक स्थायी सीट व परिषद के अस्थायी सदस्य संख्या में विस्तार की मांग की गयी है। जो कि पारित हो जाने की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के लगभग 60 वर्ष के इतिहास में इसकी सर्वोच्च निर्णायक इकाई में व्यापक परिवर्तन करेगा। कोफी अन्नान द्वारा स्थापित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल सुधार संभावनाओं से संबंधित निश्चित प्रस्ताव दिसम्बर में

विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। अन्नान कि हालही में दिये वक्तव्य में सुधारो से संबंधित प्रश्न पर इसकी तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने इरका युद्ध का उदाहरण दिया। इस युद्ध में अमरिका ने सुरक्षा परिषद के समर्थन के बगैर युद्ध प्रारम्भ कर दिया। संयुक्त राष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा सहयोग कर्ता स्थायी सदस्यता के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर चुका है और अपना समर्थन जुटा रहा है क्योंकि अस्थायी सदस्य के रूप में इसकी 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो रही है। जर्मनी की स्थायी सदस्यता के लिए अधिक से अधिक समर्थन जुटाने का प्रयत्न कर रहे हैं।<sup>2</sup> उनके अभियान को आशातीत सफलता प्राप्त हो रही है। बैठक के बाद फिशर ने कहा, “सभी चारो राष्ट्र अपने आपको योग्य उम्मीदवार मानते हैं उनकी मान्यता का आधार है कि वे संयुक्त राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, यह भी कि उनकी क्षेत्रीय भूमिका क्या रही है। □□□□ में से एक स्थायी सदस्य ब्रिटेन पहले से ही इन चारों के लिए अपना समर्थन व्यक्त कर चुका है। किन्तु पुराने क्षेत्रीय विवाद इन चारों देशों की राह आसान बनने नहीं देंगे। जर्मनी को इटली द्वारा विरोध झेलना पड़ सकता है जो कि ईराक युद्ध में अमरीका का नजदीकी मित्र है वह जर्मनी उस युद्ध का विरोध कर चुका है। पाकिस्तान के लिए भारत की उम्मीदवारी का पचा पाना बहुत मुश्किल है जो कि उसका परमाणु शक्ति सम्पन्न पड़ौसी है। जबकि ब्राजील की कोशिश का मैक्सिको व अर्जेन्टीना ठण्डा स्वागत करेंगे एवमं जापान की उम्मीदवारी को लेकर चीन की नाखुशी सामने आयी जबकि संयुक्त राष्ट्र में उसने यह कहा कि सुरक्षा परिषद के सदस्य बॉर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समान नहीं होने पर आर्थिक योगदान के आधार पर बतौर सदस्य चुन लिये जाये। महासभा को संबोधित करते हुए फोइजुली ने कहा कि, “ईराक अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में अपने देश की भूमिका को रेखांकित किया। उत्तरी कोरिया के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित मसले पर अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे कहा कि वे देश जो अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में योगदान कर सकते हैं व करने के इच्छुक हैं उन्हें सुरक्षा परिषद के निर्णय प्रक्रिया में स्थान दिया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।<sup>3</sup> जापान की उम्मीदवारी के समर्थन में उन्होंने कहा कि विश्वभर में यह अकेला ऐसा देश है जिसने परमाणु त्रासदी को झेला है। चार देशों ने यह भी कहा कि विश्व में अत्यधिक आर्थिक रूप से कमजोर महाद्वीप को भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अफ्रीकी नेता अभी विचार-विमर्श में लगे हुए कि यदि उन्हें ऐसा मौका दिया जाये कौनसा देश उनका प्रतिनिधित्व करेगा।

## भारत व जापान की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए प्रयत्न जारी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया पर चीन व अमरीका जैसे ऐतिहासिक प्रतिद्वन्द्वियों के प्रभाव को देखते हुए यह माना जा सकता है कि विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत व

जापान को दोगुना दर्जे की सदस्यता के स्थान पर ही संतोष करना पड़ेगा। इसके लिए भी अभी लम्बा इंतजार करना पड सकता है।

नवम्बर में हुई बैठक में निरीक्षक समिति को बेहद दबाव का सामना करना पडा कि एशिया महाद्वीप को वैश्विक गतिविधियों में अधिक बडा स्थान दिया जाना चाहिए। □□□□ स्थायी सदस्यों में से तीन रूस फ्रांस व यूनाटेड किंगडम को अपने पक्ष में करने में टॉकियों व दिल्ली को सफलता मिली। किन्तु चीन व अमरिका को वे अपने पक्ष में नहीं कर पाये। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में इन पाँचों के पास वीटो अधिकार है व 10 सदस्यों को क्षेत्रीय समूहों से चक्रीय आधार पर 2 वर्ष के लिए चुना जाता है।<sup>4</sup>

युद्धकाल में जापान द्वारा चीन के भू-भाग पर किये गये जबरन कब्जे से चीन अभी भी नाराज है। भारत की बढ़ती क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को लेकर उसके मन में संदेह है। अतः वह स्थिति को यथावत् बनाये रखे जाने के पक्ष में है। वही हॉल अमरीका का भी है। जबकि वांशिगटन के बाद टोकियों संयुक्त राष्ट्र का सबसे बडा वित्तीय सहयोगर्ता है। तीसरे दुनिया के देशों में चीन के पास पर्याप्त प्रभाव है। जिससे महासभा में मतदान प्रक्रिया को वह प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर यह कह सकते है कि 10-12 वर्ष पूर्व जो बहस छेडी गयी थी उस समय अमरीका व चीन की जो भूमिका रही थी उसमें आंशिक परिवर्तन भी नहीं हो पाया है। उनकी भूमिका यही है कि परिषद में यदि कोई अतिरिक्त सीटे बढ़ायी जाती है तो वह इसी अधिकार पर कि उनके पास निषेधाधिकार नहीं होगा।<sup>5</sup>

इण्डोनेशिया ब्राजील, अर्जेन्टीना, मैक्सिकों तथा संभवतया नाइजीरिया इजिप्त व दक्षिण अफ्रीका इन देशों को सदस्यता के उम्मीदवार के रूप में देखा जा सकता है और वह भी तब जब आखिरकार संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक रूप से विकसित विश्व से अपना ध्यान हटाने के लिए राजी हो जाये। सबसे अधिक लोकप्रिय जापान को प्रस्ताव रहा है। जिसके अन्तर्गत परिषद की सदस्यता को 15-24 जिसमें 10 स्थायी व 14 अस्थायी (जिनके पास वीटो का अधिकार नहीं होगा) होंगे। इस प्रकार विस्तार किये जाने की बात कही गयी है।<sup>6</sup>

## निषेधाधिकार अब उतना महत्त्वपूर्ण नहीं

साधाको ओगाटा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुधार कार्यक्रमों पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उससे भी अधिक चर्चा सुरक्षा परिषद में कितनी सीटे हो इस प्रकार के संख्यात्मक विषयों पर विशेष ध्यान

केन्द्रित किया जा रहा है। कुछ स्थितियाँ पूर्व में इस प्रकार रही हैं जब सुरक्षा परिषद प्रभावशाली साबित हुई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कई मौकों पर वह असफल रही। जहाँ तक वीटो अधिकार का प्रश्न है शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद ऐसे बहुत ही कम मौकों रहे जबकि इसे गैर जिम्मेदारी व मनमाने तरीके से लागू किया गया। हमें पिछले रिकार्ड का अध्ययन करना चाहिए कि किसने और किन विशिष्ट परिस्थितियों में इसका उपयोग किया।<sup>7</sup>

**ब्राजील, भारत, जर्मनी द्वारा सुरक्षा परिषद सुधार प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत:—** सुरक्षा परिषद में विस्तार किये जाने की मांग को लेकर ब्राजील, भारत व जर्मनी ने प्रस्ताव का प्रारूप महासभा को प्रस्तुत किया। किन्तु इस बार वे जापान का समर्थन प्राप्त नहीं कर सके। समाचार पत्रों को उपलब्ध कराये गये प्रारूप में पूर्व में प्रस्तुत किये गये प्रारूप की मांग को दोहराया गया है। इसमें सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या को 15/25 जिसके अन्तर्गत 6 स्थायी व 4 अस्थायी सदस्य लिये जाने की बात कही गयी है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का वह सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसके निर्णय सभी सरकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इसमें फिलहाल □□□□ वीटो अधिकार सहित 5 स्थायी सदस्य व 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए जाते हैं। प्रारूप के साथ प्रस्तुत की गयी टिप्पणी में ब्राजील, भारत व जर्मनी ने कहा G-4 प्रस्ताव का पुनः प्रस्तुतिकरण सुरक्षा-परिषद सुधारों को वांछित दिशा में ले जाने की प्रक्रिया है। तीनों देश G-4 की रूपरेखा के अन्तर्गत जापान से अपना सहयोग जारी रखेंगे व प्रारूप में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रस्ताव पर निकट भविष्य में तत्काल मतदान कराये जाने का उनका इरादा नहीं है। समाचार पत्रों में प्रकाशित जापान के मुख्य मंत्री परिषद सचिव शिनझों आवें ने अपने वक्तव्य में कहा 'ब्राजील, भारत व जर्मनी द्वारा की जा रही ताजा कोशिश को जापान ने अपना समर्थन नहीं दिया। क्योंकि इसके लिये आवश्यक समर्थन जुटा पाना उनके लिये असम्भव है। अदांजा लगया जा रहा है कि टॉकियों द्वारा सुरक्षा परिषद विस्तार के संदर्भ में ऐसा प्रस्ताव प्रारूप तैयार किया जा रहा है जो अमरीका को स्वीकार्य हो क्योंकि अमरीका G-4 प्रस्ताव का प्रखर विरोध करता रहा है। गत वर्ष ग्रीष्मकाल में सुरक्षा परिषद सुधार को लेकर G-4 अफ्रीकी गठबंधन व स्थायी सदस्य संख्या बढ़ाने के विरोधी देश सब ने महासभा को अलग-अलग उपायों से अवगत कराया। किन्तु समर्थन के अभाव में समर्थन के अभाव में उनमें से किसी एक पर मतदान संभव नहीं हो सका। दिसम्बर के उत्तरार्द्ध में नाइजीरिया, दक्षिणी अफ्रीका, घाना व सेनेगल ने अफ्रीकी गठबंधन का प्रस्ताव महासभा को पुनः प्रस्तुत किया। हांलाकि उन्होंने 191 देशों की सदस्यता वाली महासभा को कार्यवाही करने का अनुरोध अभी तक नहीं किया है।<sup>8</sup>

## संदर्भ सूची

1. प्रतियोगिता दर्पण :- जापान: ऐतिहासिक चुनावी फैसला, दिसम्बर 2005 पृष्ठ संख्या 877, प्रकाशक स्वदेशी बीमा बाजार, आगरा।
2. सुरक्षा परिषद योजना पर जापान का पुर्नविचार  
(हमजा हेन्दावी – ऐसोसिएटेड प्रेंस 30 सितम्बर 2005)
3. सुरक्षा परिषद विस्तार को चीन का विरोध  
कोलम्बिच वॉशिंगटन पॉस्ट 5 अप्रैल 2005
4. क्या भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलेगी?  
जे. सी. रमन 23 सितम्बर 2004
5. स्थायी सदस्यता के लिए ब्रिटेन ने भारत का समर्थन किया  
(1 जुलाई 2005, पी टी आई)
6. हम भारत का समर्थन करेंगे जी-4 प्रस्ताव का नहीं चीन  
(14 जुलाई 2005 वर्ल्ड टाइम)
7. प्रतियोगिता दर्पण: समसामयिक वार्षिकी 2007, "अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य" पृ. संख्या 89–यथावत् 90, प्रकाशक: स्वदेशी बीमा नगर, आगरा।
8. भारत के पास वीटो अधिकार होना चाहिए – पुतिन  
(नई दिल्ली 4 दिसम्बर)